बजट भाषण

2025-2026

1. आदरणीय अध्यक्ष महोदय! मैं इस सम्मानित सदन में वित्तीय वर्ष 2025–26 का बजट प्रस्तुत कर रही हूं। आज का दिन ऐतिहासिक है। यह कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली की जनता और पूरा देश आज यह देख रहा है कि दिल्ली की नई सरकार, जो कि ऐतिहासिक जनादेश के साथ चुनकर आई है, जिनको बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ दिल्ली वासियों ने वोट देकर भेजा है। उस सरकार का पहला बजट कैसा होगा? मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह बजट सिर्फ सरकारी खर्चे और आमदनी का लेखा–जोखा नहीं है बल्कि पिछले दस वर्षों में बेहाल और बदतर हुई दिल्ली को विकसित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला संकल्पित कदम है। एक ऐसी दिल्ली जो गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का संगम बने।

2. मैं और मेरी सरकार दिल्ली वासियों तथा मां यमुना का नमन करते हुए इस जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हुए इसे समुचित निभाने का संकल्प लेते हैं।

3. हमारा यह बजट बाबा साहब के समता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय और महात्मा गांधी के सर्वोदय तथा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास के सिद्धान्तों से प्रेरित है।

4. अध्यक्ष महोदय! मुझे यह बताते हुए अत्यन्त दुख की अनुभूति हो रही है कि पिछले दस सालों में विकास के हर पैमाने पर दिल्ली लगातार फिसलती चली गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, सीवर

ओवरफ्लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति और वायु प्रदूषण से भयावह दमघोटती हवांए ये सभी पिछली सरकार के शासन और नीतियों का स्पष्ट प्रमाण है। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया कार्पोरेशन ठप्प, झुग्गियों के विकास के लिए काम करने वाला विभाग DUSIB पूरी तरह ठप्प, टूटी सड़कें, गन्दा पानी, बहता सीवर

यह सब जैसे कि दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। ऐसे में सरकार का हमारे पास आना और उसको चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है परन्तु फिर भी मैं इस दो लाईनों के माध्यम से सरकार की मंशा आप सभी को बताना चाहती हूँ।

''यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है,
हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है''

5. अध्यक्ष महोदय! मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को यह बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के राज में अधिकतम बजट वर्ष 2023–24 में कागजों पर 78800 करोड़ रूपए दिखाया जा रहा था जो कि इसी सरकार के अगले वित्तीय वर्ष 2024–25 में 2800 करोड़ रूपए घटकर मात्र 76 हजार करोड़ रूपए रह गया था उसे हमने वर्ष 2025–26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले बजट के रूप में एक लाख करोड़ रूपए का प्रस्तावित किया है। जो कि पिछले साल के बजट से 31.5 प्रतिशत अधिक है एवं अपने आप में अभूतवूर्व और ऐतिहासिक है।

6. अध्यक्ष महोदय! जहां साल दर साल बजट बढ़ने के बजाय घटा, वहीं जीडीपी की दर भी पूरे देश की तुलना में कम रही। राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय कम गति से बढ़ी। यह तथ्य स्पष्ट रूप से बयान करते हैं कि पिछली सरकार में ना तो यह क्षमता थी कि वह राजस्व बढ़ा सके और ना ही यह इच्छाशक्ति थी कि वो विकास कार्यों पर ईमानदारी से खर्चा कर सकें। दिल्ली की वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि बुनियादी ढांचा एवं नागरिक सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त है। यही नही, ये आंकड़े पूरी तरह से financial mismanagement के स्पष्ट प्रमाण हैं। यहां यह कहना भी उचित होगा कि सरकारी आय इसलिए घटी क्योंकि जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वह शराब माफिया, जल बोर्ड तथा पी.डब्ल्यू.डी के ठेकेदारों के माध्यम से पिछली सरकार से सम्बन्धित जुड़े हुए लोगों को मिल रहा था। पर अब भ्रष्टाचार, कुप्रबन्धन एवं अक्षमता के दिन आपदा सरकार के साथ चले गए। हमारे एक लाख करोड़ रूपए के इस ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले Capital Expenditrure में दुगुनी बढ़ोत्तरी कर दी गई है, जो कि दिल्ली बजट के इतिहास में पहली बार हो रहा है। पिछले वर्ष के 15089.25 करोड़ की तुलना में आने वाले वित्तीय वर्ष, यह राशि 28115.48 करोड़ रूपए कर दी गई। विकसित दिल्ली के बजट में Capital Expenditrure की इस राशि का आबंटन सड़कों, नालियों, सीवर, शिक्षा सुविधाओं में सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।

7. अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने यह कहते हुए Development खर्चें कम किए थे कि उनके पास धन और संसाधनों की कमी है। विडम्बना यह है कि अगर पिछली सरकार ने दिल्ली में केन्द्र सरकार की योजनाओं को मात्र राजनीतिक कारणों से रोका न होता तो स्वास्थ्य, शहरी आवास, पानी तथा सीवर इत्यादि के विकास में पैसों की कमी कभी न होती।

8. अध्यक्ष महोदय! मैं यहां सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगी। सारा विश्व जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन पर आधारित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है और लाखों जरूरतमंद नागरिकों को इसका सीधा फायदा प्राप्त हुआ। परन्तु केन्द्र सरकार के निरंतर अनुरोध के बावजूद यह योजना दिल्ली में लागू नहीं की गई सिर्फ इसलिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की यह जिद थी कि इस योजना के आगे उनका नाम लगा दिया जाए। इस जिद का खामियाजा दिल्ली की आम जनता को उठाना पड़ा, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक के खाली खोखे पकड़ा दिए गए।

9. अध्यक्ष महोदय! इस सदन को बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस सरकार ने, कार्यभार सम्भालने के तुरन्त बाद पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का निर्णय लिया था। यह योजना शीघ्र ही लागू हो जाएगी और इसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री जन

आरोग्य योजना में केन्द्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रूपए के Insurance के साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा भी 5 लाख रूपए का अतिरिक्त Insurance किये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए लगभग 2144 करोड़ रूपए आबंटित करने का प्रस्ताव है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभार्थियों को दस लाख रूपए तक की उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

10. माननीय अध्यक्ष जी! हमने अपने घोषणापत्र में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के आशय से 16 संकल्प घोषित किए थे। महिलाओं का सशक्तिकरण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एजेंडे में प्रमुख स्थान रखता है। इसी के अनुरूप हमने यह घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमने न केवल इस योजना को ''महिला समृद्धि योजना'' के तौर पर लागू करने का फैसला लिया है बल्कि 2025–26 के दौरान इस मद में 5100 करोड़ रूपए प्रस्तावित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आबंटन को बढ़ा कर 210 करोड़ रूपए किए जाने का प्रस्ताव है। पिछली सरकार के विपरीत, हमारी सरकार की नीतियां गरीबों को गरीब बनाए रखने तथा मध्यम वर्ग को बदहाल करने वाली नहीं होंगी। ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वो सन्तु निरामयाः'' के भारतीय दर्शन से प्रेरित हमारी सरकार झुग्गी बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियों, मध्यम वर्गीय तथा उच्च वर्गीय इलाकों में रहने वाले प्रत्येक दिल्लीवासी की सुख–सुविधा और स्वास्थ्य के लिए समुचित प्रयास करेगी।

(संशोधित अनुमान 2024–25)

11. अध्यक्ष महोदय! जैसा कि मैंने पहले कहा कि पिछली सरकार के Financial Mismanagement की वजह से, पिछले साल के बजट में निर्धारित खर्च की प्रतिबद्धता, संसाधनों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकी। अतः चालू वित वर्ष आय तथा राजस्व की स्थिति को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 के संशोधित बजट अनुमानों को घटाकर 69500 करोड़ रूपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित संशोधित बजटीय अनुमानों में 54,706 करोड़ रूपए का आबंटन राजस्व व्यय और 14,794 करोड़ रूपयों का आबंटन पूंजीगत व्यय के लिए किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2024–25 के अनुमोदित बजट अनुमानों में स्थापना एवं अन्य अपरिहार्य व्यय के लिए 37,000 करोड रूपए का प्रावधान था, संशोधित अनुमानों में इसे घटाकर 36,650 करोड़ रूपए कर दिया गया है। इसी प्रकार योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए अनुमोदित 39,000 करोड़ रूपए को संशोधित अनुमानों में घटाकर 32,850 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

(वर्ष 2024–25 के लिए पूरक अनुदान मांगे)

12. महोदय, 2024–25 के दौरान संशोधित अनुमान में 163.4365 करोड़ रूपए की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं पूरक अनुदान मांगों के अनुमोदन हेतु सदन से अनुरोध करती हूं।

13. अब मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष बजट का अनुमान प्रस्तुत करती हूं।

(बजट अनुमान 2025–26)

14. मुझे फिर से यह घोषित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष प्रस्तावित बजट अनुमान बढ़कर एक लाख करोड़ रूपए का हो गया है। यह एक ऐतिहासिक वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन से ही संभव हो सका है।

15. वर्ष 2025–26 के प्रस्तावित एक लाख करोड़ रूपए के बजट की वित्तीय आपूर्ति 68,700 करोड़ रूपए के Tax Revenue से, 750 करोड़ रूपए के Non tax Revenue से, 15,000 करोड़ रूपए लघु ऋण से, 1000 करोड़ रूपए केन्द्रीय सड़क निधि से, 4128 करोड़ रूपए केन्द्र पोषित योजनाओं से, 7348 करोड़ रूपए भारत सरकार के सहायता अनुदान से तथा बाकी राशि Opening Balance से पूरा किया जाना है। इस बजट का 72 प्रतिशत राजस्व व्यय तथा 28 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए आबंटित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी सरकार के दस मुख्य संकल्प या 10 key focus areas हैं:

1. Infrastructure Development–
बुनियादी सुविधाओं – पानी, बिजली व सड़क का विकास

2. Industrial Development and Investment Promotion–
उद्योग और निवेश - समृद्धि का रास्ता, प्रगति का आधार

3. Access to Water, Sanitation, and Yamuna Cleaning-
स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान, बनेगा दिल्ली की पहचान

4. Health and Education For All-
शिक्षा गुणवत्तापूर्ण, स्वास्थ्य का विस्तार, बनेगा दिल्ली के भविष्य का आधार

5. Tourism, Art, Language and Culture Promotion–
'विरासत भी और विकास भी' की सोच के साथ दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाना

6. Expanding Social Security and Development–
गरीब एवं वंचित परिवारों को केवल सहारा नहीं शक्ति भी और विकास भी

7.Seamless Connectivity-

सार्वजनिक परिवहन का नया दौर

8. Efficient Irrigation and Flood Control-

सिंचाई में सुधार, बाढ़ का समाधान, सुरक्षित होगी राजधानी की जान

9. Power, Sustainable Development, Green Growth and Pollution Control-

हरित दिल्ली, स्वच्छ हवा, सतत विकास

10. Smart and Good Governance–

'Perform, Reform and Transform' मंत्र के साथ सुशासन

<u>Infrastructure Development– बुनियादी सुविधाओं–पानी, बिजली व सड़क का विकास</u>

1. हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से Infrastructure पर केवल बातें नहीं होंगी, बल्कि विकसित दिल्ली की मजबूत नींव डाली जाएगी! Smart Infra, Smooth Roads और Seamless Connectivity – अब यही होंगी नई दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली में सिर्फ Traffic Jams की चर्चा नहीं, Bullet Speed Development की हकीकत होगी!

2. एक समय दिल्ली के मालिक ने दिल्ली को लन्दन बनाने का सपना दिल्लीवासियों को बेचा था। लेकिन टूटी सड़कों, बढ़ते ट्रैफिक जाम, electrocutions और incomplete projects ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ पोस्टर चिपकाए, लेकिन धरातल पर विकास ठप पड़ा रहा।

3. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर यह बजट दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करने के लिए संकल्पित है। दिल्ली अब Traffic-Free Expressways, Seamless Connectivity, Elevated

Corridors और Smart Surveillance System के नए युग में प्रवेश कर रही है। यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़-घटाव नहीं, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है, जो दिल्ली को Global Infrastructure Hub बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

4. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते है, ***"We must invest in resilient infrastructure today for a better tomorrow."*** अर्थात् – "बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए। "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये भी कहते है, ***"Better infrastructure is about connecting dreams, accelerating progress."*** अर्थात् – "बेहतर बुनियादी ढांचे का मतलब सपनों को जोड़ना और विकास में तेजी लाना है।"

5. प्रधानमंत्री मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) के Central Roads Fund (CRF) और शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के Urban Development Fund (UDF) आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से infrastructure projects को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से NCR क्षेत्र के साथ दिल्ली

की कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए ₹1000 करोड़ आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है।

6. सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, दिल्ली में 2,80,000 कैमरों के अलावा 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाना भी प्रस्तावित है।

7. दिल्ली में सड़क एवं पुल अवसंरचना के सुधार के लिए ₹3843 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है।

8. योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है अर्थात, मुख्यमंत्री विकास निधि, जिसके लिए 1400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य विकास और सहायता के लिए धन आवंटित करना है और यह अनिवार्य रूप से सरकार की अन्य योजनाओं और पहलों के तहत पहले से किए गए प्रयासों का पूरक होगा।

9. 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए infrastructure projects के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत ₹1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जा रहा है।

10. आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ऐसी मज़बूत और पारदर्शी नींव रख रहे हैं जिसे कोई भी फिर से कमज़ोर न कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध और सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर, जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखे।

11. देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा झुग्गी-झोपड़ियों और जे.जे. कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी-भरकम खर्च के बावजूद इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं। यह एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

12. अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे ने कहा था - ***"वास्तविक उन्नति तभी की जा सकती है, जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ तक ही सीमित रहे।"***

13. झुग्गी-झोपड़ियों और जे.जे. कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी-झोपड़ियों और जे.जे. कॉलोनियों के विकास के लिए DUSIB को ₹696 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करते हैं, जो पिछले साल की तुलना में 157% अधिक है। CC फुटपाथ, नालियां, शौचालय, रखरखाव कार्य और महिलाओं के लिए स्नानघर जैसे

बुनियादी ढांचे के कामों के लिए मैं पिछले साल के ₹42 करोड़ रुपए के मुकाबले ₹230 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करती हूं।

14. पिछली सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभ दिलाने में विफल रही। हम इस योजना को स्वीकार करेंगे ताकि हमारे शहरी गरीबों को इसका लाभ मिल सके। इस योजना के तहत ₹20 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

15. बजट अनुमान 2025–26 में विधायक निधि (MLA-LAD) के तहत 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़कों, गलियों, स्थानीय पार्कों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

16. भोजन हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी तक दिल्ली में 100 स्थानों पर पौष्टिक और रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन की स्थापना के लिए ₹100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

17. यह बजट केवल सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर्स के निर्माण का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य को फिर से संवारने का

रोडमैप है। अब दिल्ली की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि प्रगति की धमनियां होंगी। अब दिल्ली की कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रैफिक सुधार नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का इंजन बनेगी। और अब दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ निर्माण परियोजनाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राजधानी की पहचान बनेगा।

Industrial Development and Investment Promotion– उद्योग और निवेश - समृद्धि का रास्ता, प्रगति का आधार

1. अध्यक्ष महोदय, जहाँ उद्योग फलते-फूलते हैं, वहीं समाज भी आगे बढ़ता है। जब निवेश आता है, तो न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, बल्कि रोज़गार के नए द्वार भी खुलते हैं।

2. दिल्ली, जो कभी व्यापार, संस्कृति और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी, बीते वर्षों में अव्यवस्था, लालफीताशाही और कुप्रबंधन की वजह से औद्योगिक विकास की दौड़ में पिछड़ती चली गई। बड़े उद्योग ठप पड़े रहे, व्यापारियों को नई नीतियों का इंतजार रहा और निवेशकों का भरोसा टूटता गया। लेकिन अब, दिल्ली को व्यापार और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल केंद्र बनाने का संकल्प लिया गया है।

3. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच "Ease of Doing Business" और "Make in India" की तर्ज़ पर हम दिल्ली में एक नवाचारशील, उद्यमी-अनुकूल और निवेशक-प्रेरित औद्योगिक क्रांति की नींव रख रहे हैं। यह बजट केवल नीतियों की

घोषणा नहीं, बल्कि व्यवसायियों, निवेशकों और स्टार्टअप्स को वास्तविक राहत देने का ठोस रोडमैप है।

4. भारत के संविधान निर्माता बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था: ***"आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगीकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ाने से हम रोज़गार दे सकते हैं, ग़रीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊँचा कर सकते हैं।"***

5. हमारी सरकार दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लाएगी। इससे औद्योगिक अनुपालन के मुद्दों का समाधान होगा और दिल्ली में व्यापार करने में आसानी होगी। एक Warehousing Policy को भी अंतिम रूप दिया जाएगा जो दिल्ली में सुरक्षित, संरक्षित और तेज़ Warehousing प्रदान करने के लिए उद्योगों की बड़ी ज़रूरत को पूरा करेगी।

6. उद्योग विभाग दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए regularlisation plan भी लाएगा। साथ ही, Single Window System लाया जायेगा जिससे 'Ease of Doing Business' को गति मिले।

7. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं DDA के परामर्श से Leased Industrial Properties को freehold बनाया जाएगा। बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र बहुत खराब स्थिति में हैं, इन औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य स्थितियों में सुधार के लिए developmental और redevelopmental activities के लिए एक programme बनाया जाएगा। साथ ही, अवैध एवं प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रति "Zero Tolerance" की नीति के साथ निपटा जाएगा।

8. दिल्ली में व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधियों को चलाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए Trader Welfare Board की स्थापना का प्रस्ताव है, जो दिल्ली में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान और निवारण पर काम करेगा।

9. Poultry, Apiary, small scale handicraft and handloom activities, small scale food processing आदि जैसे कुटीर उद्योगों के कौशल संवर्धन के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना को Delhi Khadi and Village Industries Board द्वारा लागू किया जाएगा। ये उद्योग अक्सर छोटे पैमाने पर विनिर्माण कार्य चलाते हैं जो स्थानीय

संसाधनों और कौशल का उपयोग करते हैं, हस्तनिर्मित सामान बनाते हैं और स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए ₹50 करोड़ का बजट रखा गया है।

10. दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निवेश के लिए अपार अवसर हैं, विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष एक Global Investment Summit आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जो इसके बाद हर दो साल में आयोजित किया जाएगा।

11. अब भ्रष्टाचार और लालफीताशाही से नहीं, पारदर्शिता और सरलता से उद्योग चलेंगे। हमारा लक्ष्य है कि फाइलों में योजनाएँ नहीं अटकेंगी, बल्कि जमीन पर उद्योग फलेंगे-फूलेंगे।

Access to Water, Sanitation, and Yamuna Cleaning-

स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान, बनेगा दिल्ली की पहचान

1. अध्यक्ष महोदय, पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं, यह सभ्यता का आधार है। स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन की गारंटी है और निर्मल नदियाँ संस्कृतियों की पहचान हैं।

2. दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को Clean Water और Sanitation उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आज मैं आपके समक्ष ₹9,000 करोड़ की ऐतिहासिक राशि के साथ जल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए हमारी दूरदर्शी योजना प्रस्तुत कर रही हूँ।

3. हमारा लक्ष्य दिल्ली की 3 करोड़ की आबादी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है, ताकि 1,290 MGD की दैनिक मांग और 1,000 MGD की वर्तमान installed capacity के बीच के अंतर को पाटा जा सके।

4. पूरी दिल्ली ने देखा कि जब गर्मी चरम पर थी, तब एक के बाद एक टैंकर घोटाले सामने आ रहे थे। हम Water tankers में GPS system लगाने जा रहे हैं और एक Android mobile app “DJB Tanker” develop करेंगे, जिससे नागरिक अपने क्षेत्र में आने वाले टैंकरों की monitoring और tracking कर सकेंगे।

5. हमने ₹10 करोड़ की लागत से जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाएँ (Consultancy) लेने का निर्णय लिया है, ताकि जल आपूर्ति और सीवरेज से जुड़ी योजनाएँ बेहतर ढंग से संचालित की जा सकें।

6. इसके अतिरिक्त, हम ₹150 करोड़ की राशि automation, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System और Intelligent Metering के लिए निवेश कर रहे हैं ताकि जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

7. ₹500 करोड़ की लागत से Sewage Treatment Plant (STP) का मरम्मत और विकास, ₹250 करोड़ की लागत से पुरानी सीवर लाइनों का प्रतिस्थापन, और ₹250 करोड़ की लागत से Water Treatment Plants में सुधार किया जाएगा।

8. सीवरेज व्यवस्था के सुधार के लिए ₹20 करोड़ की लागत से super sucker और डिकी मशीनों की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही, Wazirabad trunk sewer के नवीनीकरण (renovation) के लिए ₹10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

9. दिल्ली में गंदे नालों के जल को रोकने और उनके उपचार के लिए ₹250 करोड़ की लागत से drains को टैप करने (Tapping of Drains) की परियोजना चलाई जाएगी।

10. इसके अलावा, सीएलसी ड्रेन (CLC Drain) की मरम्मत के लिए ₹50 करोड़, अभी तक जल आपूर्ति से वंचित क्षेत्रों में पाइप्ड जल आपूर्ति के लिए ₹50 करोड़ और नजफगढ़ ड्रेन के परिवर्तन और इंटरसेप्शन के लिए ₹200 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

11. Water loss को रोकने और efficiency बढ़ाने के लिए, ₹200 करोड़ की राशि से हरियाणा से खुले open canals की जगह pipeline बिछाई जाएंगी।

12. जल संकट से निपटने के लिए हम ₹100 करोड़ की लागत से नए Borewells/Ranney Wells स्थापित करेंगे। दिल्ली के water bodies के पुनरुद्धार के लिए ₹50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

13. इसके अलावा Rainwater Harvesting के लिए ₹50 करोड़ खर्च किए जाएंगे और ₹150 करोड़ आपातकालीन जल भंडारण (Emergency Water Storage) के लिए आवंटित की गई है।

14. अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ़ करने का वादा दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली, जो कभी यमुना के निर्मल जल से सिंचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की प्यास नहीं बुझाई, बल्कि जल संकट को और गहरा किया। यमुना जी को बचाने की कसमें खाई गईं, लेकिन उसे गंदगी का नाला बना दिया गया।

15. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की Sabarmati River Front और नमामि गंगे जैसी ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर, हम दिल्ली के

जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकासोन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

16. यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। यमुना जी की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने-बाने में बहती हुई जीवनरेखा है। लेकिन दुर्भाग्यवश, पिछली सरकारें इसे स्वच्छ करने में पूरी तरह विफल रहीं। अब हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाने जा रही है ताकि यमुना जी को पुनः निर्मल और स्वच्छ बनाया जा सके।

17. यमुना जी की सफाई के लिए हम ₹500 करोड़ की लागत से 40 Decentralised Sewage Treatment Plant बनाएंगे, ताकि सीवेज का पानी उसी स्रोत पर ही treat हो जाए।

18. इसके साथ ही, मौजूदा Sewage Treatment Plant (STP) को upgrade करने का भी हमारा संकल्प है ताकि sewage treatment ki operational capacity में सुधार हो सके।

19. इसके अतिरिक्त, ₹40 करोड़ की राशि से modern machinery खरीदी जाएगी, जिसमें trash skimmer, weed harvester, dredge utility जैसी आधुनिक techniques शामिल होंगी।

20. हमारा मानना है कि दिल्ली के water और sewage infrastructure को international standards के अनुरूप बनाने के लिए और अधिक सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए, हम भारत सरकार से ₹2,000 करोड़ की financial assistance की माँग करेंगे।

21. इन पहलों के माध्यम से, हम दिल्लीवासियों से clean drinking water, sewage management और clean Yamuna का वादा करते हैं। यह केवल बजट की घोषणा नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य को जल संकट से मुक्त करने की प्रतिबद्धता है।

Health and Education For All- शिक्षा गुणवत्तापूर्ण, स्वास्थ्य का विस्तार, बनेगा दिल्ली के भविष्य का आधार

1. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती हैं। लेकिन बीते वर्षों में दिल्ली के लोग न तो बेहतर इलाज पा सके, न ही बेहतर शिक्षा। अस्पतालों में लंबी कतारें, जांच के लिए महीनों का इंतजार, स्कूलों में गिरता स्तर – यह उस बदहाल व्यवस्था की तस्वीर थी, जो सिर्फ वादों और दिखावे में उलझी रही।

   पुरानी कहावत है: "**पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया।"**

2. पिछली सरकार ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार एक हजार की आबादी पर अस्पतालों में 5 बेड उपलब्ध होने चाहिए। फिलहाल दिल्ली में एक हजार की आबादी पर 2.70 बेड उपलब्ध हैं। ऐसे में WHO के मानकों के मुताबिक दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा अभी भी कमजोर है। यही वजह है कि बड़े सरकारी अस्पतालों की ओपीडी और दवा काउंटरों पर मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं।

मरीजों को घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर होना पड़ता है। सर्जरी और जांच के लिए इंतजार करना भी बड़ी समस्या है। इसका कारण यह है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड डॉपलर, सीटी स्कैन, एमआरआइ, पीईटी-सीटी जैसी रेडियोलॉजी जांच की सुविधाओं का भी अभाव है। हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट में भी इन समस्याओं को उजागर किया गया।

3. फिलहाल 24 अस्पतालों की परियोजनाएं लंबित हैं। इनमें सात आईसीयू अस्पताल, चार नए अस्पताल और 13 मौजूदा अस्पतालों के विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 16,186 बेड बढ़ जाएंगे।

4. हमारी सरकार का लक्ष्य है की दिल्ली के हर नागरिक को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, पुरुष हो या महिला - सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ मिले। इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को मजबूत करके प्राप्त करेंगे और प्राथमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार करेंगे।

5. सभी नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सतत नीतिगत हस्तक्षेप और बुनियादी ढांचे का विकास शुरू

किया जाएगा। हम **सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः** के महामंत्र के साथ दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प करने जा रहे हैं।

6. बजट 2025-26 के प्रस्तावों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, enhancing financial accessibility, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और updating regulations करना शामिल है।

7. 400 स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर (HWC)/आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर (HWC)/आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत ₹320 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।

8. साथ ही, PM-ABHIM के अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और diagnostics को मजबूत किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ₹1666.66 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

9.इसके अलावा, हमारी सरकार AB-PMJAY के तहत वित्तीय सुरक्षा के लिए कवरेज बढ़ाएगी। इस योजना के तहत ₹147.64 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

10. स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए Ayushman Bharat Digital Mission को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत ₹9.92 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

11. हम बेहतर accountability के लिए health regulations को update करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं।

12. Alternative Healthcare की दिशा में काम करते हुए हम दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी (DSAS) का भी कार्यान्वयन करने जा रहे हैं।

13. बजट में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ₹3421 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ₹6874 करोड़ रुपये के आवंटन प्रस्तावित है।

14. अब बात करते है शिक्षा की। 2013 से पिछली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को शासन की प्राथमिकता बनाने की बात कही, लेकिन

किया इसका एक दम उलट। शिक्षा के नाम पर दिल्ली को गुमराह किया गया, और सरकार की नीतियों ने बच्चों को उनके भविष्य से वंचित कर दिया। अनगिनत छात्रों को फेल कर दिया गया और उन्हें open schools में जाने का आदेश दे दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, हर साल कक्षा 9 और 11 में 1.5 लाख से अधिक छात्र फेल कर दिए जाते हैं। बिना प्रभावी सुधारात्मक कार्यक्रमों के, संघर्षरत छात्र पीछे रह जाते हैं, जिससे स्कूल छोड़ने की दर बढ़ती है और सरकारी दावों को कमजोर कर देती है। जिन बच्चों के कंधों पर भविष्य में दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी थी, आज उन्हें पिछली सरकार की भ्रष्ट नीतियों ने लाचार कर दिया और उनके भविष्य को अन्धकार में धकेल दिया।

अध्यक्ष महोदय**, स्वामी विवेकानंद ने कहा था:, "यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, तो शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए।"**

15. हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी की हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा मिले, वो भी उनके घरों के नज़दीक।

16. सभी बच्चों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से परे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हम आगामी सत्र 2025-26 से 60 नए सीएम श्री स्कूल खोलने की घोषणा करते हैं। यह National

Education Policy (NEP) 2020 का पूर्ण अनुपालन करेंगे और इनमें National Curriculum Framework for School Education (NCFSC) 2023 लागू किया जाएगा। ये स्कूल पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर ही खोले जाएंगे। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 100 करोड़ की बजट राशि रखी गई है।

17. हमारी सरकार महामना पं. मदनमोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन की भी शुरुआत करने जा रही है। इस पहल के तहत JEE, NEET, CLAT, CA और CUET परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को professional मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

18. इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुच्छेद 4.43 के अनुरूप बनाया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ₹21 करोड़ की बजट राशि रखी गई है।

19. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप इस विजन के तहत 'राष्ट्रनीति' की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए ₹1.5 करोड़ का विशेष बजट आवंटन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के 12वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल करने वाला यह कार्यक्रम शासन, लोकतंत्र, सक्रिय नागरिकता और नीति निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करेगा। इसमें युवा संसद, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संवाद,

डिजिटल शासन, भारत के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों का वर्चुअल दौरा और सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बनें।

20. दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी। इन प्रयोगशालाओं में आधुनिक तकनीक और Artificial Intelligence का उपयोग करके अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी कई भाषाएँ सिखाई जाएँगी। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में ₹21 करोड़ की राशि प्रस्तावित है।

21. KG से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 'science of living' कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ₹1.5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

22. CBSE के मानदंडों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में 175 नई कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में ₹50 करोड़ की बजट राशि रखी गई है।

23. शिक्षा निदेशालय के लिए दिल्ली सरकार कक्षा 9 से 12 तक सभी कक्षाओं में स्मार्ट कक्षाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है, जो चरणबद्ध तरीके से कुल 7,000 कक्षाओं को कवर करेगा।

24. पहले चरण में, लगभग 2000 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा में interactive panels/projectors, audiovisual aids, and internet connectivity होगी, जिससे अधिक आकर्षक और प्रभावी शिक्षण पद्धतियाँ विकसित होंगी। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ₹100 करोड़ की राशि प्रस्तावित है।

25. शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए, कक्षा 10वीं बोर्ड के परिणामों के आधार पर कक्षा 11वीं के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 1,200 छात्रों को निशुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ₹7.5 करोड़ की बजट राशि रखी गई है।

26. कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में NEEEV (New Era of Entrepreneurial Ecosystem and Vision) कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। Entrepreneurship शिक्षा को वित्तीय और digital literacy के साथ एकीकृत करके और Experiential Learning पर जोर देकर, NEEEV छात्रों को उन कौशलों से लैस करेगा जिनकी उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था में

सुसज्जित होने की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ₹20 करोड़ की बजट राशि रखी गई है।

27. तकनीकी शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं में ₹618 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। इसमें Delhi Skill and Entrepreneurship University के लिए ₹230 करोड़ रुपए, Netaji Subhash Technical University के लिए ₹57 करोड़ रुपए, Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University के लिए ₹37 करोड़ रुपए, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women के लिए ₹21.50 करोड़ रुपए और Delhi Technical University के लिए ₹42 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हमने अपने Industrial Training Institutes (ITIs) के लिए ₹68.98 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं।

28. दिल्ली में शिक्षा संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नरेला सब-सिटी में एक Edu-City स्थापित की जा रही है। इसके लिए DDA ने भूमि आवंटित की है — (i) 160 एकड़ IGDTUW को, और (ii) 1270 फ्लैट चार विश्वविद्यालयों को अर्थात् DSEU, DPRSU, GGSIPU एवं DTU को, ताकि वे नरेला में अपने परिसरों की स्थापना या विस्तार कर सकें। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-

26 में ₹500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

29. ITI PUSA परिसर के पुनर्विकास और ITI Shahdara परिसर के निर्माण का प्रस्ताव। ITI PUSA परिसर के पुनर्विकास और ITI Shahdara के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए ₹20.65 करोड़ का प्रस्तावित बजट है।

30. प्रस्ताव किया गया है कि अधिक से अधिक कुशल लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की पहचान की जाए और उन्हें मानकीकृत प्रमाणन प्रक्रिया तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक/संगठित क्षेत्र में लाया जाए, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जाएं। इससे उनकी बाज़ार/उद्योग में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, अब तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 3.0 एवं PMKVY 4.0) के RPL घटक के अंतर्गत 34 विभिन्न कार्यों में 7155 प्रशिक्षुओं को अन्य सरकारी भागीदारों और निजी एजेंसियों के माध्यम से प्रमाणित किया जा चुका है।

31. युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्टार्ट-अप स्थापित करने तथा उन्हें नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता बनाने की दिशा में क्षमता विकसित करने के लिए State Incubation Policy के तहत 11 Incubation Centres के लिए ₹2.43 करोड़ का

बजट प्रस्तावित है। वर्तमान में, Incubation Centres में 268 Incubates कार्यरत हैं।

32. प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए कुल ₹886.15 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है – हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा।

Tourism, Art, Language and Culture Promotion– 'विरासत भी और विकास भी' की सोच के साथ दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाना

1. अध्यक्ष महोदय, मैं अपने छात्र जीवन से ही दिल्ली को काफी करीब से देखा है। मैंने इसके हर रंग देखे हैं और पाया है कि शायद ये ये दुनिया सबसे खूबसूरत शहर है। दिल्ली के रंगों को जब भी देखती हूँ, तो मुझे मिर्ज़ा ग़ालिब का वो शेर याद आता है:

"एक रोज़ अपनी रूह से पूछा, कि दिल्ली क्या है,
तो यूँ जवाब में कह गई —
ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान।"

2. दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, यह सदियों का इतिहास, कला, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत संगम है। दिल्ली में लाल किले की वीरगाथा से लेकर बंगला साहिब की अरदास तक, इंडिया गेट की शान से अक्षरधाम की दिव्यता तक, हर कोना एक अनूठी कहानी कहता है।

3. हमारी सरकार का संकल्प है – दिल्ली को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बनाना, दिल्ली की कला-संस्कृति को राष्ट्रीय

और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, और हमारी भाषाई विरासत को संरक्षित व सशक्त करना।

4. दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाने हेतु, मैं पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं के लिए पिछले वर्ष के ₹66 करोड़ की तुलना में ₹117 करोड़ का प्रस्ताव करती हूँ।

5. हम सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक यमुना नदी में नौका पर्यटन आयोजित करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस संबंध में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और DDA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना PPP मोड पर की जाएगी।

6. हम दिल्ली में Tourism के promotion & branding के लिए कदम उठाएंगे और इस उद्देश्य के लिए ₹25 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

7. पर्यटन के विशिष्ट और उभरते क्षेत्र में young professionals को तैयार करने के लिए fellowship programme आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है और इस संबंध में ₹2 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

8. दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और स्थल उपलब्ध हैं। हम इस वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि दिल्ली को फिल्म गंतव्य के रूप में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और प्रचारित किया जा सके। मैं इस उद्देश्य के लिए ₹30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश करती हूँ।

9. हम युद्ध स्मारक, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय और नए संसद भवन को शामिल करते हुए एक नया पर्यटन सर्किट भी विकसित करेंगे।

10. सांस्कृतिक शो, Food Festival, संगीत कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रमों के साथ एक वार्षिक शीतकालीन दैनिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा।

11. एक नई “Talent Hunt Scheme” शुरू की जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें मंच प्रदान करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और कलाकारों को सशक्त बनाना होगा। इसके अलावा, यह योजना दिल्ली के कलाकारों को लक्षित करेगी जिसमें संगीत, नृत्य और दृश्य कला और प्रदर्शन कला जैसे विभिन्न कला रूपों में छात्र, युवा पेशेवर और स्वयं सीखे हुए कलाकार

शामिल होंगे। इस योजना के तहत ₹5 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

12. मैं बताना चाहूँगी कि हमने मैथिली–भोजपुरी अकादमी का बजट 3.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.30 करोड़ रुपये कर दिया है।

13. इस बजट में कला संस्कृति एवं भाषा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए ₹139 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया गया है।

Expanding Social Security and Development– गरीब एवं वंचित परिवारों को केवल सहारा नहीं, शक्ति भी और विकास भी

1. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि कोई भी भूखा न सोए, कोई भी असहाय न रहे, और हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। मैंने दिल्ली की सेविका के रूप में दिल्ली की जनता के हर एक दुःख को दूर करने का प्रण ले रखा है।

   न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवम्। कामये दुःखतप्तानां, प्राणिनामार्तिनाशनम्॥
   अर्थात, मुझे न तो राज्य की कामना है, न स्वर्ग की और न ही पुनर्जन्म की। मेरी इच्छा है कि दुखी प्राणियों का कष्ट दूर हो जाए।

2. हमारी सरकार का लक्ष्य inclusive development है। आज हम जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, वह केवल संख्याओं का हिसाब नहीं, बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण और समान अवसरों की दिशा में एक ठोस कदम है। हम अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद (Integral Humanism) की मूल भावना है। हमारी

राजधानी केवल आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास का प्रतीक ही न बने, बल्कि इस विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे।

3. इसी सोच के साथ, हमने सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण के लिए अनेक योजनाएँ प्रस्तावित की हैं। इस क्षेत्र के लिए ₹10,047 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से ₹9,780 करोड़ सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और SC/ST/OBC कल्याण विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

4. इन योजनाओं के माध्यम से हम 9.50 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुँचेंगे, जिसमें 4.02 लाख वरिष्ठ नागरिक, 4.18 लाख विधवा एवं संकटग्रस्त महिलाएँ, और 1.30 लाख दिव्यांगजन शामिल हैं।

5. वित्तीय सहायता योजनाओं को और मजबूत करते हुए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है; वरिष्ठ नागरिकों (60-69 वर्ष) के लिए मासिक सहायता ₹2,500 की जा रही है; 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹3,000 की मासिक सहायता दी जाएगी। SC/ST/अल्पसंख्यक समुदायों के वरिष्ठ नागरिकों (60-69 वर्ष)

को अतिरिक्त ₹500 की मासिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, 'संकटग्रस्त महिलाओं' और 'दिव्यांगजनों' की वित्तीय सहायता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह की जा रही है। ऐसी सभी योजनाओं के लिए ₹3,227 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

6. वरिष्ठ नागरिकों को आराम और सामाजिक गतिविधियों के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु 'GIA to Recreation Centres for Senior Citizens' योजना के तहत ₹20 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

7. जैसा मैंने पहले रेखांकित किया था, महिलाओं के अवैतनिक घरेलू श्रम (unpaid domestic labour) को पहचान और सम्मान देने के लिए हमने "महिला समृद्धि योजना" शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे पात्र महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता मिलेगी। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्म-सम्मान को बढ़ाने में सहायक होगा।

8. इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए विशेष योजना बनाई गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना (MMMVY) भी शुरू की जा रही है, जिसके लिए ₹210 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को ₹21,000 तक की वित्तीय सहायता और 6 पोषण किट्स प्रदान की जाएँगी।

9. पालना - राष्ट्रीय क्रेच योजना' के तहत ₹50 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 500 पालना-आँगनवाड़ी-कम-क्रेच केंद्र स्थापित किए जाएँगे, जिससे माताएँ बच्चों के जन्म के बाद कार्यबल का हिस्सा बनी रहें।

10. इसके अतिरिक्त, 'सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2 योजना' के लिए ₹206 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, 1000 आँगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आँगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इन आँगनवाड़ी केंद्रों में बेहतर infrastructure, आधुनिक सुविधाएँ और उच्च स्तरीय service delivery सुनिश्चित किया जाएगा। Internet Wi-fi connectivity, LED स्क्रीन, water purifiers, smart learning aid, audio-visual aid और बच्चों के

holistic development के लिए अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएँगे। इन्हें अन्य सरकारी भवनों के साथ सह-स्थित (co-locate) किया जाएगा। इन आँगनवाड़ी केंद्रों को पास के सरकारी स्कूलों से जोड़ा जाएगा, ताकि बच्चों को regular schools में आसानी से स्थानांतरित किया जा सके।

11. महिलाओं को safe, secure और affordable आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सखी निवास योजना' चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल और उनके बच्चों के लिए डे-केयर सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में दिल्ली में 14 कार्यरत महिला हॉस्टल संचालित हैं, जिनमें 1,935 महिलाएँ इन सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए 2 नए 'सखी निवास' शुरू किए जाएंगे।

12. दिल्ली में बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए ₹5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत न केवल आश्रय दिया जाएगा, बल्कि vocational training और skill building कार्यक्रम भी चलाए जाएँगे, ताकि वे अपनी आजीविका स्वयं कमा सकें।

13. अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए 'डॉ. बी. आर. अंबेडकर Stipend योजना' शुरू की जा रही है। इस योजना के लिए ₹5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत दिल्ली के ITI, Skill Centres और Polytechnics में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को ₹1,000 की मासिक stipend दी जाएगी।

14. इसके अतिरिक्त, DSFDC को बेहतर करने के लिए 'GIA for Revamping of DSFDC' योजना के तहत ₹2 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

15. हमारी सरकार दिल्ली के हर गांव और किसान को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसको पूर्ण करने के लिए, विकास विभाग को कुल ₹1,157 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें ₹1,082 करोड़ विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

16. 'पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप-अप योजना' के तहत ₹4.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के

अंदर, किसानों को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत मिलने वाले ₹6,000 वार्षिक सहायता के अतिरिक्त ₹3,000 वार्षिक (₹1,000 की तीन किश्तों में) प्रदान किए जाएंगे। यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

17. दिल्ली के गांव घुमनहेड़ा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 'मॉडल गौशाला' स्थापित करने के लिए ₹40 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस गौशाला में गौ-संरक्षण, दुग्ध उत्पादन और पशु चिकित्सा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

18. दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों के समग्र विकास के लिए ₹1,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस राशि का उपयोग सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा।

Seamless Connectivity-
सार्वजनिक परिवहन का नया दौर

1. वर्तमान में, दिल्ली में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी electric bus fleet है, जिसमें 2,152 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इसमें डीटीसी के तहत 1,752 इलेक्ट्रिक बसें और DIMTS- Cluster योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 तक बेड़े में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने की उम्मीद है और इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा electric bus fleet हासिल करना है।

2. DMRC 289 स्टेशनों के साथ 394.25 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का संचालन कर रही है। चरण-4 में 03 priority corridor का 60% काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके साथ ही चरण-4 के Balanced 03 कॉरिडोर अर्थात् लाजपत नगर - साकेत जी ब्लॉक, इंद्रलोक - इंद्रप्रस्थ, रिठाला - बवाना - नरेला - नाथूपुर (कुंडली) का काम 2025-26 में शुरू किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के लिए ₹2929.66 करोड़ का आवंटन किया गया है।

3. भारत सरकार के वित्त पोषण से राजधानी में शहरी परिवहन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इन केंद्रीय वित्त पोषण परियोजनाओं के लिए ₹1,000 करोड़ का आवंटन किया गया

है।

4. दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹12,952 करोड़ का बजट परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है।

5. दिल्ली आज स्मार्ट, हरित और sustainable public transport system की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य परिवहन को अधिक सुविधाजनक, प्रदूषण-मुक्त और विश्व स्तरीय बनाना है।

Efficient Irrigation and Flood Control-
सिंचाई में सुधार, बाढ़ का समाधान, सुरक्षित होगी राजधानी की जान

1. अध्यक्ष महोदय, चाणक्य ने कहा था: **"किसी देश की प्रगति के लिए उस देश के राजा को आने वाली विपदाओं को लेकर पहले से ही सजग रहना चाहिए और उन्हें समय से पहले खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, आर्थिक प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को खत्म करना चाहिए और राजस्व की हानि को कम करने की कोशिश करनी चाहिए."**

2. दिल्ली बरसात में राहत की बजाय आफत झेलती रही है। सड़कों पर जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति, ठहरे हुए पानी में समाई गाड़ियों की हेडलाइट्स और धंसती सड़कों की तस्वीरें—यही हमारी राजधानी की पहचान बन गई है।

3. दिल्ली में waterlogging और खराब drainage system एक गंभीर समस्या रही है, जिससे हर साल बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। दिल्ली की 3 करोड़ की आबादी को हर साल बारिश के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि - दिल्ली में बरसात का मौसम ही खराब है। लेकिन असल में बरसात खराब नहीं थी, बल्कि

दिल्ली की पिछली सरकारों का प्रशासन खराब था। उन्होंने कभी भी इस समस्या की जड़ को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण दिल्ली की सड़कों पर जलभराव आम बात बन गई थी।

4. लेकिन हमारी सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (Irrigation and Flood Control Department) के लिए कुल ₹603 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से ₹315 करोड़ विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

5. इस समस्या से निपटने के लिए, हमने "बाढ़ नियंत्रण के लिए नालों के पुनर्निर्माण" (Remodeling of Drains for Flood Control) की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित की है, जिसके लिए ₹150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नालों की जल वहन क्षमता (carrying capacity) को बढ़ाना है, ताकि बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या को रोका जा सके।

6. इसके साथ ही, बाढ़ नियंत्रण के लिए हम खुले जलाशयों (open water bodies) की सफाई और Desilting की योजना भी बनाई जा रही है।

7. इसके अलावा, modern machinery की खरीद भी की जाएगी, जिससे waterlogging को नियंत्रित और flood control को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

Power, Sustainable Development, Green Growth and Pollution Control-

हरित दिल्ली, स्वच्छ हवा, सतत विकास

1. दिल्ली सरकार राजधानी के हर नागरिक को uninterrupted और affordable बिजली प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। यह बजट दिल्ली को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. इसी दिशा में बिजली विभाग को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ₹3,847 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

3. मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली के हर नागरिक को बिना किसी रुकावट के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और राजधानी की आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए आंतरिक बिजली उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है, और वह भी clean/renewable ऊर्जा स्रोतों से।

4. दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के Ministry of New and Renewable Energy के साथ MoU करने की प्रक्रिया में है,

ताकि 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' को दिल्ली में लागू किया जा सके। इस योजना के तहत दिल्ली के आवासीय उपभोक्ताओं को ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

5. इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए मेरी सरकार 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना - राज्य टॉप अप' नामक एक नई योजना ला रही है, जिसके लिए ₹50 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख आवासीय छतों को सौर ऊर्जा से लैस किया जाएगा।

6. ओवरहेड बिजली के तार न केवल शहर की सुंदरता को बिगाड़ते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरे होते हैं। इसलिए मेरी सरकार 'एचटी/एलटी ट्रांसमिशन लाइनों के स्थानांतरण' (Shifting of HT/LT Transmission Lines) योजना लेकर आई है, जिसके लिए ₹100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत सभी overhead तारों को भूमिगत किया जाएगा, जिससे दिल्ली अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक शहर बनेगा। दिल्ली अब ऊर्जा-सशक्त शहर बनने के मार्ग पर है – जहाँ हर घर रोशन रहेगा, हर उद्योग फलता-फूलता रहेगा और हरित ऊर्जा से भविष्य सँवरता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, climate change कोई दूर की चिंता नहीं, बल्कि दरवाज़े पर खड़ा संकट है। दिल्ली की हवा में घुलता ज़हर सिर्फ़ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हर नागरिक के फेफड़ों में घर करता धीमा ज़हर है। यह केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है!

7. दिल्ली की air quality और water resources को स्वच्छ और संरक्षित रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। दिल्ली को वायु और जल प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, waste management भी दिल्ली की प्रमुख समस्याओं में से एक है।

8. इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें environmental parameters की monitoring और परियोजनाओं के time bound implementation की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से, हमारी सरकार ने पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए ₹506 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जिसमें ₹422 करोड़ विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

9. “Pollution Control और Emergency measures” के तहत ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि दिल्ली में पर्यावरणीय सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

10. साथ ही, “दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी” योजना के अंतर्गत ₹20 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे RWA, NGOs और सोसाइटियों को अधिक वित्तीय सहायता दी जा सके और दिल्ली के पार्कों और बगीचों को हरा-भरा बनाया जा सके।

11. दिल्ली के हरित क्षेत्र (green cover) को बढ़ाने, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और urban biodiversity को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह अभियान बड़े पैमाने पर पूरे शहर में चलाया जाएगा और साथ ही, पहले से लगाए गए पौधों का उचित रखरखाव भी किया जाएगा।

12. इसके साथ ही, वायु प्रदूषण की real-time monitoring और data-driven decision making के लिए 6 नए CAAQM (Continuous Ambient Air Quality Monitoring) स्टेशन दिल्ली के strategic स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।

13. इतना ही नहीं, पहली बार दिल्ली में 32 Water quality Monitoring Stations स्थापित किए जाएंगे। यह स्टेशन यमुना नदी और विभिन्न नालों में लगाए जाएंगे, ताकि water quality का real-time monitoring हो सके। यहाँ advanced sensors होंगे, जो Real time प्रदूषण की निगरानी करेंगे। इन स्टेशनों से auto alerts विभिन्न विभागों को भेजे जाएंगे, जिससे समय रहते जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की कार्रवाई हो सके।

14. दिल्ली में "इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC)" स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह केंद्र air quality, water quality, noise levels, waste management जैसे विभिन्न पर्यावरणीय parameters की real-time monitoring करेगा। इससे पर्यावरणीय प्रशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकेगा।

15. हमारा यह प्रयास न केवल प्रदूषण को कम करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करेगा।

Smart and Good Governance–

‘Perform, Reform and Transform’ मंत्र के साथ सुशासन

1. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शासन/सुशासन के सम्बन्ध में कहा है—

   “हमने सत्ता के Mindset को भी बदला है। हम सेवा का Mindset लेकर आये हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टिकरण नहीं, बल्कि सन्तुष्टिकरण को अपना आधार बनाया है।”

2. उपायुक्त का कार्यालय जिला स्तर पर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय की भूमिका निभाता है। जिलाधिकारी की इस सहयोगात्मक भूमिका को सशक्त बनाने के लिए, मैं “जिला परियोजना निधि योजना” का प्रस्ताव करती हूँ, जो छोटे स्तर के उन कार्यों के लिए होगी जिन्हें त्वरित वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए मैं ₹53 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करती हूँ।

3. राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली विभिन्न आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के बीच आपदा प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एकीकृत कमांड और

नियंत्रण केंद्र का अभाव है। बेहतर संकट प्रबंधन के लिए एकल आपातकालीन नंबर प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक Emergency Operations Centre (EOC) का प्रस्ताव रखा गया है। DDMA के तहत Command Control Centres, EOC की स्थापना के लिए ₹30 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। ये केंद्र नवीनतम मशीनरी और ICT उपकरणों से सुसज्जित होंगे।

4. पिछली सिफारिशों के अनुसार बजट में स्थानीय निकायों को आवंटन वर्ष 2025-26 में स्थानीय निकाय को ₹6897 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें से ₹3,560 करोड़ रुपये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के लिए होंगे। ₹3,337 करोड़ रुपये Basic Tax Assignment (BTA) के रूप में दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ₹3,640 करोड़ रुपये स्टांप और पंजीकरण शुल्क और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में दिए जाएंगे।

5. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मौजूदा 690 कोर्ट हॉल में 200 और कोर्ट रूम जोड़कर Court Infrastructure को बढ़ाने की योजना है, खास तौर पर शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा और रोहिणी में, जिसके लिए ₹490 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। दिल्ली में न्यायिक वितरण प्रणाली में देरी को दूर करने के लिए न्यायिक अधिकारी के साथ-साथ सहायक न्यायालय

कर्मचारियों के स्तर पर आवश्यक जनशक्ति को बढ़ाया जा रहा है।

6. Hybrid System of Courts स्थापित करने के लिए ₹200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

7. हमने इस बजट में संवेदनशील मामलों और वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सहयोग से, विभाग समर्पित POCSO अदालतों के माध्यम से संवेदनशील मामलों को संभालने वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रहा है ताकि बाल पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके और विशेष NDPS अदालतों के माध्यम से ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ़ सुनवाई में तेजी लाई जा सके।

8. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न न्यायिक योजनाओं के लिए ₹927 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

9. छोटी गलियों/भीड़भाड़ वाले इलाकों में आग लगने की घटनाएं इस सरकार की प्रमुख चिंताओं में से एक हैं। इन इलाकों में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए घनी आबादी वाले इलाकों और संकरी गलियों में पहले वाहन के रूप में दो पहिया वाहनों

को लाया जाएगा। दिल्ली fire services की प्रतिक्रिया समय और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए विभाग ने भीड़भाड़ वाले और दूरदराज के इलाकों में 100 स्थानों पर छोटी दमकल गाड़ियों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है।

10. 17 Water Bowsers की खरीद। Fire services के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के पहले चरण के तहत multi articulated fire towers, aerial ladder platforms, Hazmat vans आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण खरीदे जाएंगे। 24 multi utility वाहनों में नवीनतम तकनीक का उपयोग करके उच्च दबाव पंप स्थापित किए जाएंगे। आग की दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील/तत्काल प्रतिक्रिया के विश्लेषण के लिए वाहनों में लाइव कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली Fire services में इन पूंजीगत योजनाओं के लिए ₹110 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

11. इस बजट प्रस्ताव में, मौजूदा Delhi Fire Station मुख्यालय भवन को बहुमंजिला बनाने का भी प्रस्ताव है।

12. डिस्पैच में उच्चतम स्तर की सटीकता सुनिश्चित करने, Delhi Fire Service Control Room का upgradation. AI

आधारित समाधानों के लिए प्रावधान करने और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के सरलीकरण और स्वचालन के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी।

13. दिल्ली Fire services के तहत पूजीगत परियोजनाओं के लिए ₹125 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

14. दिल्ली में Home Guards Volunteers की अधिकृत संख्या को मौजूदा 10,285 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार, अतिरिक्त 15000 Home Guards Volunteers दिल्ली पुलिस, डीटीसी और अन्य विभागों के समन्वय से सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देंगे।

15. दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को समयबद्ध तरीके से नौकरी देने के इरादे से रोजगार मेला आयोजित करने के लिए ₹2 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

16.अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की एक बड़ी आबादी है, जो कई तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश अनिवार्य सेवाओं से जुड़े हैं। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, घरेलू सहायक, auto taxi drivers आदि

हैं, जिन्हें अब तक किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। इन कामगारों का शोषण करने वाले व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा शोषण रोकने के लिए, हमारी सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए एक कल्याण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करती हूँ।

17. दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत शिकायतों के प्रभावी और समयबद्ध निवारण के लिए एक ऐप विकसित करने के लिए ₹15 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये जाते हैं जो NDMC क्षेत्र में चल रहे NDMC-311 के समान होगा। इस ऐप के अंतर्गत कॉल सेंटर शिकायतें प्राप्त करने के माध्यमों में से एक होगा। इस संबंध में कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर 1031 को ऐप के साथ एकीकृत किया जाएगा।

18. विभिन्न क्षेत्रों के नए युवा दूरदर्शी लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से Chief Minister's Young Visionaries Innovation Programme शुरू करने के लिए ₹10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के युवा दूरदर्शी लोगों की ऊर्जा और नए विचारों को प्राप्त करना है, जिन्हें नीति और निर्णय लेने में लागू किया जाएगा, ताकि दिल्ली

को एक स्मार्ट, स्वच्छ, देखभाल करने वाला और समृद्ध महानगर बनाया जा सके।

19. दिल्ली जेल के तत्वावधान में एक सोसायटी की स्थापना की जाएगी। यह सोसायटी विभिन्न कौशल प्रदान करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से कैदियों के समग्र कौशल को विकसित करके उनके सुधार और पुनर्वास के लिए काम करेगी और जेलों की विभिन्न फैक्ट्रियों और विनिर्माण इकाइयों के कामकाज को पेशेवर बनाएगी। तिहाड़, रोहिणी और मंडोली के जेल परिसरों में निर्मित उत्पादों को दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाले कार्यालयों, मंत्रालयों और विभागों द्वारा खरीद में वरीयता दी जाएगी।

20. कैदियों के कल्याण के लिए मौजूदा तिहाड़ जेल परिसर में भीड़भाड़ कम करने के लिए, मौजूदा तिहाड़ जेल परिसर को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए नए जेल परिसर के विकास की एक नई योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत परामर्श और सर्वेक्षण कार्य के लिए ₹10 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।

21. साथ ही, 01-04-2025 से Renovation & Alteration of Lampur Restriction/Detention Centre का प्रस्ताव है | इस योजना के तहत ₹20 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।

Vision

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारी सरकार के Vision में और योजनाएं भी है जिनका संक्षेप में मैं उल्लेख करना चाहूंगी।

1.मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना

हमारे व्यापारी भाई-बहनों के लिए, जिनकी मेहनत और ईमानदारी से दिल्ली का व्यापार फल-फूल रहा है, हम 'विवाद से विश्वास' योजना लाएंगे। इस योजना के तहत पुराने VAT मामलों का सौहार्द पूर्ण समाधान किया जाएगा, ताकि व्यापारियों को लंबित मुकदमों से मुक्ति मिले। यह योजना न केवल व्यापारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि करेगी। रामराज्य में न्याय और शांति का आदर्श था, हम उसी आदर्श के साथ व्यापारी वर्ग के साथ खड़े हैं।

2.योजना के लाभ केवल पात्रों तक पहुंचे

हमारी सरकार का एक अहम उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिले, जो वास्तव में पात्र हैं। 'आप'

सरकार ने दिल्ली की योजनाओं को वोट बैंक राजनीति के तहत चलाया, जिससे न सिर्फ दिल्लीवासियों के अधिकार हनन हुए, बल्कि योजनाओं का लाभ अपात्र लोगों तक भी पहुंचा। हम अब एक सशक्त सत्यापन अभियान चलाएंगे, ताकि योजनाओं का लाभ केवल असली दिल्लीवासियों तक पहुंचे, और दिल्ली की सीमाओं के बाहर से आए विशेष रूप से बांगलादेशी और रोहिंग्या जैसे अवैध प्रवासियों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिले।

3.दिल्ली में दो नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए हम दो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। इससे दिल्लीवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा मिलेगी और युवाओं को मेडिकल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जहां 'आप' सरकार ने कभी भी स्वास्थ्य क्षेत्र में ठोस कदम नहीं उठाए, वहीं हम दिल्लीवासियों को बेहतर इलाज और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं। दिल्ली को एक स्वास्थ्य और शिक्षा का केंद्र बनाना हमारा उद्देश्य है, और

यह पहल दिल्ली के युवाओं को मेडिकल क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देगी।

4.राज्य अतिथि गृह की कमी को समाप्त किया जाएगा

यह अत्यंत शर्मनाक है कि दिल्ली में आज तक राज्य अतिथि गृह नहीं है, जो किसी भी राज्य की प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए। हम शीघ्र ही दिल्ली में एक भव्य राज्य अतिथि गृह बनाएंगे, जिससे दिल्ली में आने वाले अतिथियों को उचित सम्मान और सुविधाएं मिल सकें।

5.दिल्ली में ऑडिटोरियम और स्टेडियम खोले जाएंगे

हमारी सरकार दिल्ली में मनोरंजन और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर ऑडिटोरियम और स्टेडियम का निर्माण करेगी। ये ऑडिटोरियम और स्टेडियम न केवल खेलों के प्रति रुचि को बढ़ाएंगे, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगे। हम एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे, जहां हर युवा अपनी प्रतिभा का सम्मान पाए, और हर नागरिक को अपनी क्षमता को साबित करने के लिए मंच मिले

6. ISBT:

हम दिल्ली में आनंद विहार ISBT और सराय काले खाँ ISBT को Redevelop करेंगे और द्वारका में एक नया ISBT खोलेंगे।

Summing Up:

1. अध्यक्ष महोदय, यह बजट कोई isloated या random document नहीं है। बल्कि इसमें हर एक चीज़ का balanced mix है। इसमें innovation और infrastructure की ऊँची उड़ान का लक्ष्य है, तो वंचितों के लिए विशेष आवंटन और अत्याधुनिक गौशाला जैसे ज़मीनी हकीकतों का भी ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर - इस बजट में ऊंचाई भी है, और गहराई भी है!
2. आज इस पावन अवसर पर, जब मैं दिल्ली की जनता के लिए इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत कर रही हूँ, तो यह केवल एक वार्षिक वित्तीय योजना नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य का खाका है। यह बजट आत्मनिर्भर दिल्ली के सपने को साकार करने का संकल्प है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और उनके 'विकसित भारत' के विजन से जुड़ा हुआ है।

3. अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने कुछ objectives तय किए हैं। इस बजट से दिल्ली अब सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि प्रगति की राजधानी बनेगी। अब घोषणाओं की जगह, योजनाओं पर अमल होगा। दिल्ली अब वादों की नहीं, इरादों की राजधानी बनेगी।

4. Double Engine की सरकार नई दिल्ली को Bullet Train की गति से आगे लेकर जाएगी और दिल्ली देश के 'Growth Engine' के रूप में उभर कर सामने आएगा।

5. अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं दिल्ली का इतिहास देखती हूँ तो मुझे मशहूर शायर बशीर बद्र का वो शेर याद आता है:

"दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है
जो भी गुज़रा है उस ने लूटा है।"

6. चेयरमैन सर, दिल्ली को विदेशी आक्रांताओं द्वारा दर्जनों बार उजाड़ा गया। चाहे मंगोल हो या अफ़ग़ान, मुग़ल हो या अँगरेज़ - सबने दिल्ली

को लूटा और उजाड़ कर चले गए। दिल्ली का ऐसा ही हाल पिछले कुछ सालों में यहाँ की राज्य सरकारों ने भी किया।

7. दिल्ली, एक ऐसा शहर है जिसने बार-बार खुद को मिटते और संवरते देखा है। इतिहास गवाह है कि चाहे तैमूर का कहर हो, नादिर शाह की लूट हो या अहमद शाह अब्दाली की बर्बरता—हर बार दिल्ली ने अपने घावों को भुलाकर, फिर से अपने वैभव को प्राप्त किया है।

8. दिल्ली का ये शहर Bharatiya या Sanatan Resilience का प्रतीक रहा है। इसे जब जब उजाड़ा गया, ये तब तब उठ कड़ी हुई। दिल्ली राष्ट्रीय चेतना और पुनर्निर्माण की प्रतीक है। दिल्ली फिर से उठ खड़ी हुई है और पुनर्निर्माण की राह पर चल चुकी है।

9. चेयरमैन सर, दिल्ली कभी सिर्फ इमारतों का शहर नहीं रही, यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ खंडहर भी इतिहास लिखते

हैं, और दीवारें भी कहानियाँ कहती हैं। जिन्होंने इसे लूटा, वो खुद मिट गए, लेकिन दिल्ली हर बार और ज्यादा बुलंद होकर खड़ी हुई।

10. आज फिर दिल्ली उठ खड़ी हुई है – अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने भविष्य को पुनर्निर्माण की नींव पर गढ़ने के लिए।

11. बीते कुछ वर्षों में, दिल्ली फिर से लूट और कुप्रबंधन का शिकार हुई। जनता की कमाई को लूटने वाले, झूठे वादों और खोखले दावों से सत्ता तक पहुंचे। दिल्ली की तिजोरी को खाली करी, समृद्धि को मिट्टी में मिला दिया, संस्कृति की पहचान को मिटाया गया, विकास को ठप किया गया और दिल्लीवासियों के हक को लूटा गया।

12. लेकिन अब, नई सोच, नए संकल्प और ईमानदार नेतृत्व के साथ, दिल्ली फिर से उठ खड़ी होगी। आज का बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि दिल्ली के पुनर्जन्म की आधारशिला है। अब हर संसाधन दिल्ली के नागरिकों के हित में लगेगा, हर नीति पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बनाई

जाएगी। हमने ठाना है कि दिल्ली सिर्फ एक महानगर नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति और सुशासन की पहचान बनेगी।

13. यह बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि दिल्ली के पुनर्जन्म का शंखनाद है। अब दिल्ली न थमेगी, न रुकेगी—यह दौड़ेगी, यह चमकेगी, यह इतिहास रचेगी!

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथै - अर्थात, कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं। इसी भावना के साथ हमारी सरकार दिल्ली की जनता की सेवा करेगी और मेहनत में कोई कमी नहीं रखेगी चाहे कुछ भी हो जाए।

14. अध्यक्ष महोदय मैं अपने बजट भाषण का समापन इन पंक्तियों से करना चाहूंगी:

"हवा का रूख बदल देने का हौसला भी है ताकत भी,
निभाते हैं अगर कोई भी वादा कर लिया हमने।

सफर अपना किसी तूफान के डर से नहीं रुकता, इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने।"

15. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं, बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती हूँ।

भारत माता की जय!

****